संख्या-54/2020/176/26-3-2020

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 31 मार्च 2020

विषय:-**चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय/राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों/कोचिंग सेन्टर के अनुरक्षण/मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1912/स0क0/ विकास/छात्रावास/अनुरक्षण/ 2019-20, दिनांक-13.01.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-132/2019/2220/26-3-2019, दिनांक-29.05.2019 एवं शासनादेश संख्या-214/2019/4209ए/26-3-2019, दिनांक-04.10.2019 द्वारा अनुरक्षण सम्बन्धी निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-132/2019/2220/26-3-2019, दिनांक-29.05.2019 एवं शासनादेश संख्या-214/2019/4209ए /26-3-2019, दिनांक-04.10.2019 को निरस्त करते हुये उक्त शासनादेशों के माध्यम से निर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति को निम्नानुसार संशोधित कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रूपये लाख में)

क्र0सं0	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय/छात्रावास/ कोचिंग सेन्टर का नाम	प्रस्तावित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, देवरिया	77.58	20.95
2	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, सेवरही कुशीनगर	13.31	13.31
3	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, लखनऊ	48.95	20.94
4	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सेखुईकला, बलरामपुर	23.85	23.85
5	04 नग राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, इटौरा आगरा	53.56	17.45
6	राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, जजी का मैदान, आजमगढ़	34.71	3.50
	योग-	**251.96**	**100.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1)-निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0सी0एल0डी0एफ0, लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(4)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व मंे अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(7)-कार्यदायी संस्था द्वारा अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश के आलोक में लो0नि0वि0 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा।

(8)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात मरम्मत कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(9)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(10)-जिस मद में धनराशि अन्तरित की जा रही है, उस मद में धनराशि की उपलब्धता निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण मद के निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृसं0-54/2020/176 (1)/26-3-2020 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4-सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7-प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0।
9-गार्डफाइल

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।